

राज्य सरकार योजनाएँ : 2021-22

राज्य	योजना/कार्यक्रम	मुख्य बिन्दु/उद्देश्य
उत्तर प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना पंचामृत योजना मातृभूमि योजना बाल श्रमिक विद्या योजना 	<p>विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु। इसका उद्देश्य गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग करना है। इसके तहत विकास कार्यों में 50% लागत का वहन सरकार द्वारा किया जायेगा। 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों, अनाथों, श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा हेतु।</p>
मध्य प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> CM राशन आपके द्वार योजना लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना रोजगार सेतु योजना 	<p>इसका उद्देश्य हर महीने अपने गाँवों में जनजातीय समुदाय के लाभार्थियों को PDS राशन का मासिक कोटा प्रदान करना है। बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। इस तहत राज्य सरकार MSME स्टार्ट-अप के लिए 50 लाख ऋणों को रु. 1 लाख प्रति वर्ष 3% ब्याज सब्सिडी और अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए बैंक ऋण गारंटी प्रदान करेगी। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना (उमरिया जिले के पुलिस द्वारा)</p>
छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> मुख्यमंत्री मितान योजना राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना कौशल्य मातृत्व योजना 	<p>इस योजना के तहत निवासी अपने दरवाजों पर जन्म, जाति, आय और विवाह प्रमाण पत्रों की डिलीवरी सहित लगभग 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के भूमिहीन कृषि कार्य करने वाले नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6000 रुपये दिए जाएंगे। इसके तहत अब राज्य में दूसरी पुत्री के जन्म पर 5000 रु. की राशि दी जायेगी।</p>
पश्चिम बंगाल	<ul style="list-style-type: none"> परय शिक्षालय परियोजना माँ की रसोई योजना 	<p>इसके तहत प्राईमरी छात्रों को खुले में पढ़ाया जाएगा। गरीबों और निराश्रितों के लिए 5 रु. में भोजन उपलब्ध कराने के लिए।</p>
ओडिशा	<ul style="list-style-type: none"> घर पर पोषण योजना आर्शिवाद योजना 	<p>अविकसित और कमजोर विकास वाले बच्चों एवं एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को घर-घर जाकर भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु। कोविड अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रख-रखाव के लिए।</p>
कर्नाटक	<ul style="list-style-type: none"> जन स्पंदन योजना जन सेवक योजना 	<p>जनता के शिकायतों के निवारण हेतु। सरकारी सेवाओं को नागरिकों के दरवाजे तक लाने के लिए।</p>
गुजरात	<ul style="list-style-type: none"> वतन प्रेम योजना गो ग्रीन योजना 	<p>इसके तहत गुजराती 60% का धनराशि देकर पसंद के परियोजनाओं और एजेंसियों को ले सकेंगे। औद्योगिक कर्मचारियों को बैटरी चालित दुपहिया वाहनों की खरीद पर छूट प्रदान करना।</p>
झारखंड	<ul style="list-style-type: none"> SAHAY योजना गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 	<p>माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खंल प्रतिभाओं को पोषित करने हेतु। शिक्षा के प्रति उत्साहित युवाओं को आर्थिक मदद पहुँचाने के लिए कम ब्याज पर 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जायेगा।</p>
केरल	<ul style="list-style-type: none"> STREET परियोजना 	<p>पर्यटकों को राज्य के पर्यटन स्थलों की विविधता के बारे में जानकारी देना।</p>
तमिलनाडु	<ul style="list-style-type: none"> पुधुमई पेन योजना मुख्यमंत्री नाश्ता योजना मीनदम मंजपई योजना 	<p>सरकारी स्कूलों से उच्च शिक्षा संस्थानों में लड़कियों के नामांकन अनुपात को बढ़ाना। 27 जुलाई 2022 के 15445 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में यह योजना लागू की गई है। प्लास्टिक के थैलियों को सीमित कर कपड़ों के थैलों को बढ़ावा देना।</p>
अरुणाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> आत्मनिर्भर कृषि/बागवानी योजना 	<p>कृषि/बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभागों को 60-60 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।</p>
तेलंगाना	<ul style="list-style-type: none"> आसरा पेंशन योजना नेथन्ना बीमा योजना 	<p>यह वृद्धों, विधवाओं और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन की कल्याणकारी योजना है। इसे बुनकरों के कल्याण के लिए शुरू किया गया है।</p>

राज्य	योजना/कार्यक्रम	मुख्य बिन्दु/उद्देश्य
राजस्थान	<ul style="list-style-type: none"> ■ महिला निधि योजना ■ इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी यो ■ चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ■ बैक टू वर्क योजना ■ मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 	<p>महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु। इससे शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को जीवनयापन करने में मदद मिलेगी। इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख का वार्षिक बीमा मिलेगा। इसके तहत तीन वर्ष के भीतर 15000 महिलाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, SC तथा ST के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु।</p>
महाराष्ट्र	<ul style="list-style-type: none"> ■ जिहला योजना 	<p>जेल में बंद कैदियों को (3 साल से अधिक) 50000 रु. तक का पर्सनल लोन दिया जाएगा।</p>
हरियाणा	<ul style="list-style-type: none"> ■ चिराग योजना ■ चारा-बिजाई योजना ■ ई-अधिगम योजना ■ मातृशक्ति उद्यमिता योजना ■ खेल नर्सरी योजना 2022-23 ■ एक ब्लॉक, एक उत्पाद योजना 	<p>इसके तहत 1.8 लाख वार्षिक से कम आय वाले परिवार के बच्चों को कक्षा दूसरी से बारहवीं तक निजी स्कूल में मुफ्त प्रवेश दिया जायेगा। इस योजना का उद्देश्य गौशालाओं को खेती और चारे की आपूर्ति करने वाले किसानों को रु. 10000 हजार प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत हरियाणा बोर्ड के कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्र 2 GB इंटरनेट डाटा के साथ मुफ्त टैबलेट प्राप्त करने के पात्र होंगे। इस योजना के तहत जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय रु. 5 लाख से कम है, उन्हें वित्तीय संस्थानों के द्वारा रु. 3 लाख तक के नरम ऋण तक पहुँच प्रदान की जायेगी। निजी/सरकारी शिक्षण संस्थानों और खेल संस्थानों में खेल नर्सरी स्थापित की जाएगी। ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा ब्लॉक को औद्योगिक दृष्टि से जोड़ना।</p>
दिल्ली	<ul style="list-style-type: none"> ■ श्रमिक मित्र योजना 	<p>इसके तहत दिल्ली में सभी निर्माण श्रमिक सरकारी योजनओं का लाभ उठा सकेंगे।</p>
आंध्र प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> ■ फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट ■ YSR यंत्र सेवा योजना 	<p>ग्रामीण अबादी में लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से एक डॉक्टर को प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध कराना। किसानों को कम लागत पर कृषि में उपयोग की जाने वाली मशीनरी उपलब्ध कराना।</p>
उत्तराखंड	<ul style="list-style-type: none"> ■ उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना ■ हिम प्रहरी योजना ■ दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना ■ घसियारी कल्याण योजना 	<p>खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। यह योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है जिसका उद्देश्य लोगों के पलायन को रोकना है। राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना साथ ही 500 दूध विक्री केन्द्र खोलना। पहाड़ी क्षेत्रों की ग्रामीण महिलाओं का बोझ कम करने के लिए पशुओं के लिए घर तक चारा उपलब्ध कराना।</p>
जम्मू-कश्मीर	<ul style="list-style-type: none"> ■ परवाज योजना 	<p>जल्दी खराब हाने वाले फलों और सब्जियों को कार्गो के माध्यम से बाजार तक पहुँचाना।</p>
हिमाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> ■ नारी को नमन योजना 	<p>इसके तहत राज्य की बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं को 50% की छूट दी जाएगी।</p>
लद्दाख	<ul style="list-style-type: none"> ■ कुनस्योम योजना 	<p>विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण व तकनीक उपलब्ध कराने हेतु।</p>
असम	<ul style="list-style-type: none"> ■ विद्या रथ-स्कूल ऑन व्हीलस योजना ■ स्व-निर्भर नारी योजना ■ मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचोनी योजना 	<p>आर्थिक रूप से कमजोर विकलांग बच्चों को मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। यह असम में स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने की योजना है। कोविड के कारण अपने माता-पिता दोनों को खो देने वाले बच्चों का वित्तीय सहायता हेतु।</p>
बिहार	<ul style="list-style-type: none"> ■ मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना ■ मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना 	<p>इसके अंतर्गत व्यक्तियों को हिरासत में लेने की जगह उनके लिए पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की गई है जिसमें उपचार, पारिवारिक सुदृढीकरण और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा है। महिलाओं को नया रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख की राशि प्रदान की जायेगी।</p>
पंजाब	<ul style="list-style-type: none"> ■ लोक मिलनी योजना ■ मेरा घर मेरे नाम योजना 	<p>जन संपर्क बढ़ाना तथा राज्य के लोगों की शिकायतों के निवारण हेतु मंच प्रदान करना। इस योजना के तहत गाँवों और शहरों के लाल डोरे के भीतर आने वाले घरों में रहने वाले लोगों को मलिकाना हक दिए जाएंगे।</p>
त्रिपुरा	<ul style="list-style-type: none"> ■ अर्न विद लर्न स्कीम ■ CM चा श्रमि कल्याण प्रकल्प योजना 	<p>योजना का उद्देश्य उन छात्रों को नामांकित करना है जिन्होंने कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्कूल छोड़ दिया था। राज्य के 7000 चाय बगान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए।</p>